



राष्ट्रीय शिक्षा नीति का परिचय, चुनौतियां एवं समाधान

Harish jatol

भारतीय शिक्षा नीति का परिचय :-

श्रेष्ठतम शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न विकल्पों की खोज हेतु

स्वतंत्रता के पश्चात् विभिन्न आयोगों का गठन किया गया यथा – राधाकृष्णन आयोग (1948), मुदालियर

आयोग (1953), कोठारी आयोग (1964), स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम शिक्षा नीति में बदलाव सन 1968, उसके पश्चात् 1986 तथा इसमें कुछ संशोधन सन 1992 में किया गया था। नई शिक्षा नीति 2020 को गांव, पंचायत के स्तर से लेकर सभी जिलों के स्तर पर सलाह मशवरा कर कस्तूरी रंजन (भूतपूर्व वैज्ञानिक ISRO) की अध्यक्षता में तैयार किया गया है इसके अंतर्गत MHRD Ministry of Human Resource Department के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय आता है जिसका नाम बदलकर Ministry of Education (शिक्षा मंत्रालय) कर दिया गया है।

नई शिक्षा नीति 2020 का परिचय :-

नई शिक्षा नीति में 10 + 2 को बदलकर अब चार भागों में विभाजित किया गया है 5 + 3 + 3 + 4 जिसमें पहला चरण फाउंडेशनल स्टेज, दूसरा चरण प्रीप्रेटरी, तीसरा चरण मिडिल स्कूल तथा चौथा चरण सेकेंडरी स्कूल होगा।

I. प्रथम चरण Foundational Stage :-

यह चरण 5 वर्ष का होगा जिसको दो भागों में विभाजित किया गया है शुरुआत के 3 वर्षों में विद्यार्थी आंगनबाड़ी, प्री-स्कूल, बालवाटिका इत्यादि में अध्ययन करेगा। इसके अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होगा विद्यार्थियों का स्कूल व शिक्षा के प्रति डर को दूर करना व शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करना है जिसमें लगभग 3 से 6 वर्ष के विद्यार्थी होंगे वह इस चरण में विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया जाएगा।

दूसरे भाग में विद्यार्थी कक्षा 1 एवं 2 का अध्ययन करेंगे जिसके अंतर्गत के अंतर्गत संपूर्ण शिक्षा स्थानीय भाषा में होगी। जिससे विद्यार्थी को शिक्षा संबंधित समस्या नहीं होगी एवं स्थानीय भाषा में होने से उनकी समझ में ज्ञान में वृद्धि होगी जिसमें विद्यार्थी अपने आस-पड़ोस एवं स्थानीय भाषा को समझ कर अपना अध्यापन कार्य आरंभ करेगा।

II. द्वितीय चरण Preparatory Stage :-

यह चरण 3 वर्ष का होगा जिसमें विद्यार्थी कक्षा 3 कक्षा 4 एवं कक्षा 5 में अध्यापन कार्य करेगा इन कक्षाओं का अध्यापन भी स्थानीय भाषा में करवाया जाएगा और कक्षा 3 से परीक्षा का आयोजन आरंभ होगा।

III. तृतीय चरण Middle Stage :-

यह चरण 3 वर्ष का होगा जिसमें विद्यार्थी कक्षा 6,7 एवं 8 का अध्यापन करेगा इस स्टेज में विद्यार्थी कंप्यूटर का ज्ञान सीखेगा तथा इसके साथ ही विद्यार्थी को वोक्ेशनल नॉलेज अथवा टेक्निकल नॉलेज भी दिया जाएगा जैसे- सिलाई, बढाई, कुकिंग, मैकेनिक इत्यादि जिसके विद्यार्थी को अंक भी प्रदान किए जाएंगे। जिसमें गणित, विज्ञान तथा कला विषय के अतिरिक्त विद्यार्थी को किसी भी एक भारतीय भाषा को पढ़ना होगा जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू आदि। :-

IV. चतुर्थ चरण Secondary Stage :-

यह चरण 4 वर्ष का होगा जिसमें विद्यार्थी कक्षा 9, 10, 11 एवं 12

का अध्ययन करेगा इस स्टेज में विभिन्न विषय Multiple subject में से अपने पसंदीदा विषय चुनकर विद्यार्थी अध्ययन कार्य आरंभ करेगा। इस स्टेज में विद्यार्थी के तार्किकता का बोध पर फोकस किया जाएगा जिसमें परीक्षा प्रणाली को वार्षिक के स्थान पर सेमेस्टर प्रणाली में आयोजित किया जाएगा

Graduation :-

स्नातक की पढ़ाई विद्यार्थियों को 4 वर्ष में पूर्ण होगी जिसमें विद्यार्थी यदि 1 वर्ष में अध्ययन कर बीच में ही कॉलेज छोड़ देता है तो विद्यार्थियों को 1 वर्ष का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा वहीं विद्यार्थी 2 वर्ष पूर्ण करने पर उसे एडवांस्ड डिप्लोमा दिया जाएगा तथा 3 वर्ष पूर्ण करने पर विद्यार्थी को डिग्री प्रदान की जाएगी उसके पश्चात यदि विद्यार्थी किसी खास विषय का गहन अध्ययन करना चाहता है तो उसे 1 वर्ष पश्चात उसे ग्रेजुएशन विद रिसर्च का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। यदि किसी कारणवश विद्यार्थी स्नातक की शिक्षा को मध्य में ही छोड़कर चला जाता है तो कुछ वर्ष पश्चात विद्यार्थी उसी स्थान से अपनी शिक्षा को आरंभ कर सकता है जहां से उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी।

Post Graduation :-

पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एक तथा दो वर्ष का होगा जिस विद्यार्थी का ग्रेजुएट 4 वर्ष का हुआ है उसे पोस्ट ग्रेजुएट 1 वर्ष के लिए तथा जिन विद्यार्थियों ने ग्रेजुएशन 3 वर्ष में पूर्ण किया है उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट दो वर्ष का होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चुनौतियां एवं समाधान

जैसा कि विदित है कि हाल ही में भारत में शिक्षा नीति 2022 को लागू किया गया है यह शिक्षा नीति शिक्षा में नवाचार, सुधार एवं शिक्षा में कौशल के विकास के लिए निर्मित की गई। यह एक उच्च तथा गुणवत्तापूर्ण नीति है इस नीति का हाल ही में लगभग पूरे भारतवर्ष में इसको लागू कर दिया गया है एवं राज्य स्तर के आधार पर इनका संचालन किया जा रहा है।

वैसे ही राजस्थान के लगभग हर यूनिवर्सिटी, सरकारी महाविद्यालय एवं निजी महाविद्यालय में इस शिक्षा नीति 2020 का संचालन किया जा रहा है इस शिक्षा नीति को लोगों तक पहुंचाना एवं लोगों को इस शिक्षा नीति के बारे में एक चुनौती पूर्ण कार्य है क्योंकि कहीं वर्षों से चली आ रही पुरानी शिक्षा नीति से हटकर नई शिक्षा नीति का संचालन करने एवं क्रियान्वयन एवं उपयुक्त सुधार के लिए आवश्यक है कि हर व्यक्ति एवं विद्यार्थी, अध्यापक को इस शिक्षा नीति को समझना आवश्यक है।

इस शिक्षा नीति से उन विद्यार्थियों को अत्यधिक लाभ मिलेगा जो विद्यार्थी पहले महाविद्यालय में अध्ययन करने के पश्चात किसी कारणवश महाविद्यालय से वंचित रह जाते थे और उन्हें वापस पुनः महाविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए नए सिरे से अध्यापन कार्य शुरू करना होता था वही इस शिक्षा नीति के अंतर्गत इस प्रकार के फार्मूले को अपनाया गया है जिसमें कोई भी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को किसी भी वक्त छोड़कर पुनः वही से वापस आरंभ कर सकता है।

इस शिक्षा नीति के तहत एक महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि विद्यार्थी पुरानी शिक्षा नीति के तहत अध्यापन को समझ रहे हैं एवं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत महाविद्यालय में सेमेस्टर प्रणाली को आरंभ किया गया है इस सेमेस्टर प्रणाली में वर्ष के प्रत्येक तीन माह में किसी न किसी रूप में एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। जिससे विद्यार्थी बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। वही विद्यार्थियों को इस शिक्षा नीति से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं है जिससे विद्यार्थी इस सेमेस्टर प्रणाली में अपने आप को ढालने में असक्षम महसूस कर रहे हैं हाल ही में महाविद्यालय में आयोजित मिडिल ट्रस्ट एवं असाइनमेंट जमा करवाने के लिए विद्यार्थियों की कम रुचि एवं अनुपस्थिति को देखकर यह बात सामने आई है कि विद्यार्थियों को इस सेमेस्टर प्रणाली की पर्याप्त जानकारी प्राप्त नहीं है। वहीं विद्यार्थियों का पुरानी शिक्षा नीति के तहत यह रवैया रहा है कि वह महाविद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात कुछ ही दिनों तक महाविद्यालय में उपस्थित होते हैं एवं पुनः एग्जाम के दिन एग्जाम देने के लिए आ जाते हैं वही यह सेमेस्टर प्रणाली एवं नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों के नियमितीकरण का एक साधन बनेगी जिससे विद्यार्थी महाविद्यालय में नियमित अध्यापन एवं अध्ययन कार्य कर सकेंगे। जिससे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा एवं लोगों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। वही इस शिक्षा नीति में लोगों को किताबी ज्ञान एवं केवल डिग्रियां प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं रखेगी वहीं लोगों को एक उचित मार्गदर्शन, व्यवहारिक ज्ञान, कौशल विकास आदि का भी मौका मिलेगा।

नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन देने के साथ-साथ निम्न कक्षाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को भी संपूर्ण लाभ मिलेगा जिसमें विद्यार्थियों को कक्षा पांच तक की संपूर्ण शिक्षा अपनी मातृभाषा में दी जाएगी एवं उनके साथ में ही उन्हें व्यावहारिक एवं कौशल विकास संबंधित अध्यापन कार्य भी करवाया जाएगा। जिससे वह विद्यालयों से निकलकर अपने लिए एक उचित एवं व्यवहारिक तथा सफलता प्राप्त करने की और अग्रसर होंगे।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक महत्वपूर्ण समस्या एवं चुनौती यह है की उच्च शिक्षा के अंतर्गत महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे छात्रों की पुरानी शिक्षा नीति के अंतर्गत 1 ईयर जिसका शुल्क विद्यार्थी को एक बार ही देना पड़ता था लेकिन नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सेमेस्टर प्रणाली लागू हो जाने से वर्ष में दो बार परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जिससे विद्यार्थियों को दो बार परीक्षा शुल्क देना पड़ता है जिससे उन पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यालय में विद्यार्थी को कक्षा 9 से ही अपनी इच्छा के अनुसार पसंदीदा विषय को चुनकर अपने भविष्य के लिए मार्ग को सुनिश्चित करना होगा। यह एक बड़ी चुनौती है कि विद्यार्थी इस उम्र में अपने लिए एक उचित मार्ग को किस प्रकार चुनेंगे क्योंकि इस उम्र में विद्यार्थियों की समझ एवं सोच का इतना विकास नहीं होता है जितना कॉलेज के विद्यार्थियों में होता है। वही विद्यार्थी पारिवार, समाज एवं अन्य के दबाव में आकर उनकी इच्छा के अनुसार विषय का चयन करेगा जिससे भविष्य में उन्हें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है।

एक अन्य समस्या यह है कि इस शिक्षा नीति में विद्यार्थी विभिन्न वर्गों से अलग-अलग विषय का चुनाव कर एक ग्रुप बना सकता है जिसमें विद्यार्थियों को अध्यापन कार्य करना पड़ेगा इसके लिए भी एक महत्वपूर्ण समस्या यह है कि विद्यार्थी भविष्य में किस प्रकार के व्यक्तित्व को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए उसे किसी एक फील्ड में निपुण व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेनी होती है लेकिन इस शिक्षा नीति में विद्यार्थी स्वयं ही एक अलग समूह का निर्माण करेगा जिसमें से विज्ञान वर्ग, कला वर्ग एवं वाणिज्य वर्ग से भी विषय का चयन कर सकता है इसीलिए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यालय महाविद्यालय एवं अन्य अध्यापन कार्यशालाओं में एक काउंसलर की नियुक्ति या परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जानी चाहिए जिससे वह विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर उन्हें सही मार्ग प्रदान कर सके जिससे वह यह बता सके कि भविष्य में वह किस प्रकार के विषय का चयन करें जिससे वह अपने सपनों को पूरा कर सकें।